Test Cloud

Daily करेंट अफेयर्स

21 जुलाई 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. BIS ने नए संशोधन के तहत जुलाई 2025 से 9 कैरेट सोने के आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है।

18 जुलाई, 2025 को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (MoCAF&PD) के तहत भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने BIS अधिनियम, 2016 के तहत संशोधन संख्या 2 जारी करके 9 कैरेट सोने के आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया, जो जुलाई 2025 से प्रभावी होगा।

• यह नया नियम भारत में स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों के मानकों को विनियमित करने वाले BIS अधिनियम, 2016 के अंतर्गत BIS संशोधन संख्या 2 के माध्यम से लागू किया गया है। हॉलमार्किंग, मानकीकृत चिह्नों और ट्रेसेबिलिटी के माध्यम से शुद्धता, उत्कृष्टता और प्रामाणिकता प्रमाणित करके उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करती है।

• नवीनतम आदेश के अनुसार, 9-कैरेट (375 ppt) सोने को आधिकारिक तौर पर हॉलमार्क योग्य ग्रेड की सूची में शामिल कर लिया गया है। इससे बीआईएस द्वारा अनुमोदित शुद्धता ग्रेड की कुल संख्या आठ हो गई है, जिनमें 24 कैरेट (999 ppt), 24 KS (995 ppt), 23 कैरेट (958 ppt), 22 कैरेट (916 ppt), 20 कैरेट (833 ppt), 18 कैरेट (750 ppt), और 14 कैरेट (585 ppt) शामिल हैं।

• नए नियमों के अनुसार, सोने की घड़ियाँ, पेन और वैध मुद्रा के सिक्के हॉलमार्किंग की ज़रूरतों से बाहर हैं। केवल 24KF (कैरेट गोल्ड - फ्लैट) या 24KS (कैरेट गोल्ड - स्ट्रक) शुद्धता वाले सोने के सिक्कों की अनुमति है, और इनका निर्माण विशेष रूप से टकसालों या BIS-अनुमोदित रिफाइनरियों द्वारा किया जाना चाहिए।

Key Points:-

(i) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (MoCAF&PD) के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने जुलाई 2025 से 9 कैरेट सोने के आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है। इससे AHCs (परख एवं हॉलमार्किंग केंद्रों) के माध्यम से शुद्धता की गारंटी बढ़ेगी, उपभोक्ताओं का विश्वास मज़बूत होगा और BIS के अनिवार्य ढाँचे का विस्तार भारत भर के 361 ज़िलों तक होगा।

(ii) नए दिशानिर्देशों का पालन न करने पर बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत दंड हो सकता है, जिसमें दो साल तक की कैद या ₹1 लाख से ₹5 लाख तक का जुर्माना, या असत्यापित सोने की वस्तु के मूल्य का दस गुना तक का जुर्माना शामिल है। प्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए, 40 करोड़ से ज़्यादा आभूषणों पर अब 6 अंकों का हॉलमार्क विशिष्ट पहचान (HUID) अंकित है, जिसे बीआईएस केयर ऐप के ज़रिए सत्यापित किया जा सकता है।

(iii) अब गोल्ड बार प्रमाणन के लिए रिफाइनरियों को लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (LBMA) या भारत के राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। यह BIS हॉलमार्किंग प्रथाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाता है ताकि पारदर्शिता, पता लगाने की क्षमता और सोने की गुणवत्ता में उपभोक्ता विश्वास बढ़े।

2. तमिलनाडु दिवस 2025 मद्रास राज्य का नाम बदलने के उपलक्ष्य में 18 जुलाई को मनाया गया।

18 जुलाई 2025 को, तमिलनाडु सरकार ने 1967 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सी.एन. अन्नादुरई द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णय को याद करने के लिए तमिलनाडु दिवस मनाया, जिसमें उन्होंने मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु करने का प्रस्ताव रखा था - जिसका अर्थ है "तमिलों की भूमि" - जो तमिल पहचान, संस्कृति और क्षेत्रीय गौरव की पुष्टि करने वाला एक ऐतिहासिक कदम था।

• सी.एन. अन्नादुरई की सिफ़ारिश के बाद, मद्रास राज्य का नाम बदलने के प्रस्ताव को भारतीय संसद ने आधिकारिक रूप से मंज़ूरी दे दी। इस कदम को भाषाई और सांस्कृतिक गौरव की स्थापना में एक मील का पत्थर माना गया, जिसने तमिलनाडु को अपनी तमिल विरासत में निहित एक राज्य के रूप में स्थापित किया।

Key Points:-

(i) मूलतः, मद्रास राज्य 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया था, जिसने भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया था। इसमें वर्तमान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्से शामिल थे।

(ii) 2022 में, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली DMK सरकार ने 18 जुलाई को आधिकारिक तमिलनाडु दिवस घोषित किया, जिससे एआईएडीएमके सरकार के पहले के फैसले को पलट दिया गया, जिसने 1 नवंबर को इस दिवस के लिए चुना था। इस बदलाव का उद्देश्य प्रशासनिक पुनर्गठन पर तमिल पहचान के महत्व को उजागर करना था।

3. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मुंबई के NFDC कॉम्प्लेक्स में पहले IICT परिसर का उद्घाटन किया।

18 जुलाई, 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (सूचना एवं प्रसारण; इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT; रेलवे के प्रभारी) और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने संयुक्त रूप से मुंबई के पेडर रोड स्थित राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC) परिसर में भारत के पहले भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (IICT) परिसर का उद्घाटन किया।

• मंत्री वैष्णव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर विकसित ₹400 करोड़ की लागत वाला IICT परिसर, IIT और IIM की तर्ज पर बनाया गया है। इसमें अत्याधुनिक कक्षाएँ, मीडिया लैब, पोस्ट-प्रोडक्शन सुइट और एनीमेशन, VFX, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (XR) के लिए विशेष क्षेत्र उपलब्ध हैं।

• उन्होंने गूगल, मेटा, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एडोब, WPP जैसी वैश्विक तकनीकी दिग्गजों

के साथ IICT की उद्योग साझेदारी और यॉर्क विश्वविद्यालय के साथ एक शैक्षणिक समझौता ज्ञापन पर ज़ोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि चार और विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ समझौते चल रहे हैं। परिसर सितंबर 2025 में 300 छात्रों के अपने पहले बैच का स्वागत करेगा।

• मुख्यमंत्री फडणवीस ने मुंबई को भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था की राजधानी बनाने की राज्य की महत्वाकांक्षा को रेखांकित किया और वेव्स शिखर सम्मेलन की पहलों के समर्थन के लिए ₹150 करोड़ के महाराष्ट्र कोष की घोषणा की। उन्होंने वेव्स इंडेक्स के मूल्यांकन में ₹93,000 करोड़ से ₹1 लाख करोड़ की वृद्धि का उल्लेख किया, जो मुंबई के रचनात्मक क्षेत्र की क्षमता को पुष्ट करता है।

Key Points:-

(i) इस कार्यक्रम में IICT लोगो का अनावरण, 17 रचनात्मक-तकनीकी पाठ्यक्रमों का शुभारंभ और भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय (NMIC) के भीतर गुलशन महल में भारत मंडप का उद्घाटन भी हुआ।

(ii) इसके अतिरिक्त, एक एकीकृत फिल्म एवं TV हब स्थापित करने के लिए प्रसार भारती और महाराष्ट्र फिल्म, मंच एवं सांस्कृतिक विकास निगम लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(iii) भविष्य में, गोरेगांव स्थित फिल्म सिटी में 10 एकड़ के भूखंड पर एक पूर्ण IICT परिसर की योजना बनाई गई है, जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। अगले चरण के इस परिसर का लक्ष्य भारत के सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक-प्रौद्योगिकी संस्थानों में से एक बनना है, जो कौशल-आधारित नवाचार के लिए सरकार के प्रयासों को और मज़बूत करेगा।

4. प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार और पश्चिम बंगाल में 12,600 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिससे बुनियादी ढांचे, रेल, IT और ऊर्जा क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा।

18 जुलाई, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी (बिहार) और दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) का दौरा किया और बुनियादी ढांचे, रेलवे, IT, ऊर्जा, मत्स्य पालन आदि क्षेत्रों से जुड़ी कुल 12,600 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

• उन्होंने दरभंगा में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) सुविधाओं और पटना के STPI में एक अत्याधुनिक इनक्यूबेशन सेंटर का शुभारंभ किया। ग्रामीण विकास की अन्य पहलों में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत मछली पालन केंद्र और बुनियादी ढाँचा शामिल हैं।

• मोतिहारी में, प्रधानमंत्री मोदी ने आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत ₹160 करोड़ की घोषणा की और दीनदयाल अंत्योदय योजना-NRLM के माध्यम से लगभग 61,500 महिला-नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को ₹400 करोड़ जारी किए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रति परिवार 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने और मखाना बोर्ड के गठन की सराहना की।

Key Points:-

(i) दुर्गापुर में, प्रधानमंत्री मोदी ने 5,400 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को समर्पित किया, जिसमें बांकुरा और पुरुलिया में BPCL द्वारा 1,950 करोड़ रुपये की सिटी गैस वितरण परियोजना, दुर्गापुर स्टील थर्मल और रघुनाथपुर पावर स्टेशनों पर 1,457 करोड़ रुपये की फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) रेट्रोफिट, पुरुलिया-कोटशिला रेल लाइन का दोहरीकरण (390 करोड़ रुपये) और सेतु भारतम के तहत दोहरे रोड ओवरब्रिज शामिल हैं।

(ii) दोनों राज्यों में रैलियों को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की शासन शैली को प्रतिद्वंद्वी दलों के विपरीत बताया—पश्चिम बंगाल में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC या TMC) की आलोचना की और जनता दल (यूनाइटेड) या JD (U) के नेतृत्व में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समावेशी विकास की सराहना की। ये दौरे बिहार विधानसभा चुनावों और पश्चिम बंगाल में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के प्रचार अभियान के लिए भी महत्वपूर्ण रहे।

(iii) प्रधानमंत्री मोदी ने इस क्षण को पूर्वी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया और इसके विकास के इंजन के रूप में परिवर्तन का उल्लेख किया। रेल, सड़क, ऊर्जा, IT और मत्स्य पालन में निवेश 'विकसित भारत' के व्यापक दृष्टिकोण का समर्थन करता है, साथ ही अमृत भारत एक्सप्रेस और एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्क को मज़बूत करता है।

5. महाराष्ट्र पशुधन और मुर्गीपालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया।

11 जुलाई 2025 को, महाराष्ट्र पशुधन और मुर्गीपालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। पशुपालन मंत्री पंकजा मुंडे की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इस ऐतिहासिक निर्णय का उद्देश्य पशुपालन-आधारित आजीविका पर निर्भर ग्रामीण परिवारों के लिए समान सब्सिडी और वित्तीय लाभ सुनिश्चित करना है।

- **नीति में औपचारिक रूप से डेयरी, बकरी पालन, सूअर पालन और मुर्गी पालन को कृषि के अंतर्गत शामिल किया गया है। पात्रता मानदंडों में 25,000 पक्षियों तक के ब्रॉयलर फार्म, 50,000 पक्षियों वाले लेयर फार्म, 45,000 क्षमता वाली हैचरी, 100 पशुओं वाली डेयरी इकाइयाँ, 500 पशुओं वाले बकरी/भेड़ फार्म और 200 पशुओं वाले सूअर फार्म शामिल हैं - जिनमें छोटे और मध्यम स्तर के पशुपालक शामिल हैं।**

- **अनुमान है कि महाराष्ट्र भर में 76.41 लाख पशुपालक परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। इस मान्यता से उत्पादकता में वृद्धि और संरचित सहायता तक पहुँच के माध्यम से सालाना ₹7,700 करोड़ की आय होगी, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हज़ारों अनौपचारिक पशुधन इकाइयों को वैधानिकता मिलेगी, जिन्हें आधिकारिक मान्यता और संस्थागत लाभों का अभाव है।**

Key Points:-

(i) महाराष्ट्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में पशुपालन का योगदान 24% है, जो फसल कृषि के 12% से दोगुना है। पशुपालन को कृषि के दर्जे के साथ जोड़ने से इसके आर्थिक महत्व और रोजगार क्षमता को मान्यता मिलती है, खासकर राज्य भर के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के भूमिहीन और सीमांत किसानों के लिए।

(ii) पात्र किसानों को अब कृषि शुल्क दरों पर बिजली मिलेगी और वे सौर सब्सिडी योजनाओं और पंजाबराव देशमुख ब्याज सब्सिडी योजना के लिए पात्र होंगे, जिसमें ऋणों पर 4% ब्याज छूट दी जाएगी। ग्राम पंचायतों के करों को युक्तिसंगत बनाया जाएगा, जिससे सभी औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त पशुपालन इकाइयों में एकरूपता सुनिश्चित होगी।

(iii) यह सुधार नीति आयोग की 2021 की सिफारिशों के अनुरूप है, जिसमें ग्रामीण संकट को कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए पशुधन क्षेत्र में संरचित सुधारों की वकालत की गई है। महाराष्ट्र का लक्ष्य निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण नवाचार को बढ़ावा देना और टियर-2 और टियर-3 रोजगार सृजन करना है, जिससे अन्य भारतीय राज्यों को भी इसी तरह की समावेशी कृषि नीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

INTERNATIONAL

1. स्विट्जरलैंड ने ऐतिहासिक भारत-EFTA व्यापार समझौते के अनुसमर्थन को अंतिम रूप दिया।

जुलाई 2025 में, स्विट्जरलैंड ने भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के बीच व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) की आधिकारिक रूप से पुष्टि की, जिससे सभी चार EFTA देशों के बीच प्रक्रिया पूरी हो गई और इसके कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया।

• स्विट्ज़रलैंड द्वारा अनुसमर्थन, TEPA को पूर्ण रूप से लागू करने की दिशा में अंतिम चरण है, क्योंकि EFTA के अन्य सदस्य देश - नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन - पहले ही अपनी मंज़ूरी प्राप्त कर चुके हैं। इसके साथ ही, यह समझौता अक्टूबर 2025 में लागू होने की राह पर है, जिससे व्यापार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे।

• TEPA किसी यूरोपीय व्यापार समूह के साथ भारत का पहला मुक्त व्यापार समझौता है। 15 वर्षों की बातचीत के बाद 10 मार्च, 2024 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित यह समझौता भारत और EFTA देशों के बीच व्यापार, निवेश और सहयोग के व्यापक क्षेत्रों को कवर करता है।

• इस समझौते का एक प्रमुख लक्ष्य व्यापार बाधाओं को दूर करना और वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को बढ़ावा देना है। यह भागीदार देशों के बीच बाज़ार पहुँच बढ़ाने, सतत विकास, निवेश सुगमता और तकनीकी सहयोग पर भी ज़ोर देता है।

Key Points:-

(i) TEPA के तहत अनुमानित प्रमुख आर्थिक प्रभाव अगले 15 वर्षों में EFTA देशों द्वारा भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है।

(ii) इस समझौते में 14 अध्याय हैं जो बौद्धिक संपदा, उत्पत्ति के नियम, विवाद समाधान और स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता मानकों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं।

(iii) भारत में EFTA के सबसे बड़े निवेशक, स्विट्जरलैंड ने अपनी आर्थिक उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि की है। भारत में स्विस निवेश 2000 में CHF 515 मिलियन (लगभग ₹5,935 करोड़) से बढ़कर 2024 तक CHF 10 बिलियन (लगभग ₹1.07 लाख करोड़) हो गया है, जिसमें 330 से अधिक स्विस कंपनियाँ इंजीनियरिंग, फार्मा और सेवाओं जैसे विविध भारतीय क्षेत्रों में सक्रिय हैं।

BANKING & FINANCE

1. वेल्थ कंपनी को 74.41 ट्रिलियन रुपये के भारतीय म्यूचुअल फंड सेक्टर में प्रवेश के लिए SEBI की मंजूरी मिल गई है।

18 जुलाई 2025 को, पैंटोमैथ ग्रुप की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द वेल्थ कंपनी एसेट मैनेजमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI – Securities and Exchange Board of India) से म्यूचुअल फंड (MF) कारोबार शुरू करने की अंतिम मंज़ूरी मिल गई।

• इस मंज़ूरी के साथ, कंपनी अब द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड (MF) के नाम से भारत के म्यूचुअल फंड क्षेत्र में प्रवेश करेगी।

• इस मंज़ूरी के साथ, द वेल्थ कंपनी MF अब भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की सबसे युवा एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) बन गई है। यह SEBI द्वारा MF उद्योग में भागीदारी और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम है, जहां जुलाई 2025 तक लगभग 50 AMC सक्रिय रूप से कार्यरत हैं।

Key Points:-

(i) द वेल्थ कंपनी MF अपने मूल संगठन पैंटोमैथ ग्रुप की वित्तीय सेवाओं में स्थापित विशेषज्ञता का लाभ उठाएगी और एक अनुशासित एवं शोध-आधारित निवेश दृष्टिकोण अपनाएगी। यह रणनीति शहरी निवेशकों के साथ-साथ टियर-3 और ग्रामीण बाजारों में भी निवेश के अवसरों को सुलभ बनाने में मदद करेगी।

(ii) भारत का म्यूचुअल फंड क्षेत्र, जिसकी मौजूदा बाजार मूल्य ₹74.41 ट्रिलियन से अधिक है, खुदरा निवेशकों की बढ़ती भागीदारी, SIP प्रवाह और वित्तीय साक्षरता के कारण तीव्र गति से बढ़ रहा है। द वेल्थ कंपनी जैसे नए खिलाड़ियों का प्रवेश प्रतिस्पर्धा और उत्पाद विविधता को बढ़ावा देगा, जिससे सभी वर्गों के निवेशकों को लाभ होगा।

(iii) कंपनी का नेतृत्व समावेशी आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो सरकार के वित्तीय भागीदारी विस्तार के लक्ष्य से मेल खाता है। इसके व्यावसायिक मॉडल में डिजिटल-प्रथम प्लेटफ़ॉर्म, निवेश शिक्षा कार्यक्रम और कम पहुंच वाले क्षेत्रों के लिए विशेष उत्पाद शामिल होंगे।

2. ऑरम प्रॉपटेक SEBI की मंजूरी के साथ सूचीबद्ध SM-REIT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई।

जुलाई 2025 में, ऑरम वेंचर्स समूह के हिस्से, ऑरम प्रॉपटेक लिमिटेड को भारत के पहले सूचीबद्ध लघु और मध्यम रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (SM-REIT) को लॉन्च करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से मंजूरी मिली, जिसका नाम AMSA SM REIT निवेश ट्रस्ट है।

- **नियामक अनुमोदन 18 जुलाई, 2025 को जारी एक औपचारिक SEBI पंजीकरण प्रमाणपत्र के माध्यम से प्रदान किया गया, जिससे ऑरम देश की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई, जो नए सेबी ढांचे के तहत SM-REIT प्लेटफॉर्म संचालित करेगी। इस उपलब्धि ने भारतीय खुदरा निवेशकों के लिए आंशिक रियल एस्टेट निवेश के द्वार खोल दिए हैं।**

- **ऑरम का AMSA SM REIT व्यक्तिगत निवेशकों को कार्यालय भवनों, सह-कार्यशील स्थानों और खुदरा दुकानों जैसे किराया-उत्पादक प्रीमियम वाणिज्यिक अचल संपत्ति में भाग लेने की अनुमति देगा - म्यूचुअल फंड या REITs के समान स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध और कारोबार की जाने वाली इकाइयों के माध्यम से।**

Key Points:-

(i) SM-REIT मॉडल विशेष रूप से पूर्ण और आय-उत्पादक रियल एस्टेट परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। यह कम जोखिम और स्थिर किराये के रिटर्न सुनिश्चित करता है, जिससे यह वाणिज्यिक संपत्ति निवेश में खुदरा स्तर की भागीदारी के लिए एक अधिक सुरक्षित और विनियमित मार्ग बन जाता है।

(ii) SM-REITs के लिए SEBI के दिशानिर्देश पारदर्शिता, नियमित मूल्यांकन और प्रकटीकरण मानदंडों के अनुपालन को अनिवार्य बनाते हैं। इन मानदंडों का उद्देश्य आंशिक रियल एस्टेट निवेश क्षेत्र में निवेशकों का विश्वास और संस्थागत-स्तरीय शासन को बढ़ावा देना है।

(iii) इस लॉन्च के साथ, ऑरम प्रॉपटेक भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी बदलाव का नेतृत्व कर रहा है, जो छोटे निवेशकों के लिए संस्थागत-गुणवत्ता वाली व्यावसायिक संपत्तियों तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाता है। यह पूंजी बाजारों को गहरा करने और खुदरा भागीदारी के लिए नए परिसंपत्ति वर्गों को पेश करने के SEBI के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप भी है।

ECONOMY & BUSINESS

1. भारत के बीमा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जेएफएसएल और एलियांज ने 50:50 पुनर्बीमा संयुक्त उद्यम बनाया।

प्रदान करके जोखिम प्रबंधन में अधिक कुशलता से मदद करेगा। इससे देश में एक अधिक लचीले और विविधीकृत बीमा बाजार को बढ़ावा मिलेगा।

(ii) पुनर्बीमा संयुक्त उद्यम के अतिरिक्त, दोनों कंपनियों ने भारत में सामान्य और जीवन बीमा व्यवसायों के लिए 50:50 संयुक्त उद्यम बनाने के लिए एक गैर-बाध्यकारी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जो भारतीय बीमा मूल्य श्रृंखला में दीर्घकालिक सहयोग के लिए व्यापक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

जुलाई 2025 में, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की सहायक कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (JFSL) ने भारत के बढ़ते बीमा पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के उद्देश्य से 50:50 घरेलू पुनर्बीमा संयुक्त उद्यम (JV) स्थापित करने के लिए अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एलियांज यूरोप बी.वी. के माध्यम से एलियांज समूह के साथ एक बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए।

- **यह पुनर्बीमा संयुक्त उद्यम '2047 तक सभी के लिए बीमा' के राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक बीमा दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार है। इसका उद्देश्य देश के जोखिम प्रबंधन ढाँचे को मज़बूत करना और विभिन्न क्षेत्रों एवं जनसांख्यिकी में बीमा उत्पादों की पहुँच बढ़ाना है।**

- **यह साझेदारी एलियांज की वैश्विक पुनर्बीमा विशेषज्ञता और जेएफएसएल की घरेलू वित्तीय ताकत और डिजिटल क्षमताओं को एक साथ लाती है, जिससे भारतीय बीमा कंपनियों को नवीन, प्रौद्योगिकी-संचालित पुनर्बीमा समाधान प्रदान करने के लिए एक मजबूत ढांचा सुनिश्चित होता है।**

Key Points:-

(i) यह पुनर्बीमा संयुक्त उद्यम भारत में प्राथमिक बीमा कंपनियों को बेहतर अंडरराइटिंग क्षमताएँ, उच्च जोखिम क्षमता और प्रतिस्पर्धी पुनर्बीमा मूल्य निर्धारण

MOUs and Agreement

1. NIEPID और जय वकील फाउंडेशन ने बौद्धिक विकलांग बच्चों (CwID) के लिए एक समान पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए साझेदारी की है।

जुलाई 2025 में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (MSJE) के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (NIEPID) ने मुंबई, महाराष्ट्र स्थित जय वकील फाउंडेशन (JVF) के साथ एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग का उद्देश्य देश भर में बौद्धिक दिव्यांग बच्चों (CwID) के लिए एक मानकीकृत और संरचित शिक्षा मॉडल प्रस्तुत करना है।

- **इस समझौता ज्ञापन पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (MSJE) के सचिव राजेश**

अग्रवाल की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए और यह जय वकील फाउंडेशन द्वारा विकसित पाठ्यक्रम और कार्यान्वयन ढाँचे "दिशा अभियान" के क्रियान्वयन का एक हिस्सा है। इस मॉडल को NIEPID द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसे भारत भर के स्कूलों और शिक्षण केंद्रों में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (CwIDs) की शिक्षा में एकरूपता और गुणवत्ता लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

• NIEPID DISHA पाठ्यक्रम, जिसे अब आधिकारिक तौर पर अपनाया जा चुका है, एक बहुस्तरीय शैक्षिक मॉडल है जिसमें एक शोध-समर्थित बहु-संवेदी पाठ्यक्रम, एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और एक शिक्षक प्रशिक्षण ढाँचा शामिल है। 2019 में NIEPID द्वारा प्रमाणित, यह ढाँचा व्यक्तिगत शिक्षा योजनाओं (IEPs) के लिए एक मूल्यांकन चेकलिस्ट को एकीकृत करता है, जो प्रत्येक बच्चे की विकासात्मक आवश्यकताओं के आधार पर अनुकूलित शिक्षण मार्ग प्रदान करता है।

• यह सहयोग NIEPID की तकनीकी और शोध विशेषज्ञता को जय वकील फाउंडेशन की क्षेत्र-आधारित कार्यान्वयन क्षमताओं के साथ जोड़ता है। साथ मिलकर, उनका लक्ष्य एक ऐसा मापनीय और एकसमान पाठ्यक्रम मॉडल तैयार करना है जो विशेष रूप से भारत भर के शहरी और ग्रामीण, दोनों परिवेशों में CwID की विशिष्ट शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया हो।

Key Points:-

(i) इस साझेदारी के तहत, JVF द्वारा विकसित महत्वपूर्ण संसाधन - जिसमें NIEPID दिशा मूल्यांकन चेकलिस्ट, मल्टीसेंसरी पाठ्यक्रम, NIEPID DISHA डिजिटल पोर्टल और एक संरचित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं - पूरे देश में विशेष स्कूलों, समावेशी शिक्षा केंद्रों और पुनर्वास संगठनों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ii) यह पहल समावेशी शिक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करती है और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) जैसे वैश्विक ढाँचों के अनुरूप है। विशेष रूप से, यह सुलभ शिक्षण उपकरण सुनिश्चित करके SDG 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए समानता को बढ़ावा देकर एसडीजी 10 (असमानताओं में कमी) को आगे बढ़ाती है।

(iii) DISHA अभियान पहल न केवल CwID शिक्षा की गुणवत्ता और एकरूपता में सुधार लाएगी, बल्कि प्रशिक्षित शिक्षकों, डिजिटल पाठ वितरण और सुसंगत मूल्यांकन उपकरणों का एक राष्ट्रीय नेटवर्क भी तैयार करेगी। यह समावेशी शिक्षा को एमएसजेई के अंतर्गत राष्ट्रीय नीति ढाँचों के साथ एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और विशेष शिक्षा क्षेत्र में साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेपों की ओर एक बदलाव का प्रतीक है।

2. UAE-भारत CEPA परिषद ने द्विपक्षीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए BHU के अटल इनक्यूबेशन सेंटर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

जुलाई 2025 में, UAE-भारत व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) परिषद, जिसे UICC के रूप में भी जाना जाता है, ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित अटल इनक्यूबेशन सेंटर - महामना फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (AIC-MFIE-IM-BHU) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

• इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच स्टार्टअप और नवाचार सहयोग को मजबूत करना है, विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों में उभरते नवाचार केंद्रों में।

• UICC के निदेशक अहमद अलजनेबी और AIC-MFIE-IM-BHU के प्रभारी प्रोफेसर पी.वी. राजीव के बीच इस समझौता ज्ञापन पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए। यह साझेदारी दोनों देशों की सतत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण और इनक्यूबेटरों, मार्गदर्शकों और पूंजी को जोड़कर सीमा पार उद्यमिता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

• इस समझौते के माध्यम से, AIC-BHU में वर्तमान में इनक्यूबेट किए गए 110 से अधिक स्टार्टअप्स को प्रमुख विकास क्षेत्रों में संस्थागत अनुभव और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के अवसर प्राप्त होंगे। इनमें स्वास्थ्य सेवा, कृषि प्रौद्योगिकी (एग्री-टेक), स्वच्छ ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े अन्य क्षेत्र और स्टार्टअप-अनुकूल उद्योग शामिल हैं।

Key Points:-

(i) इस साझेदारी का एक प्रमुख आकर्षण UAE-भारत स्टार्ट-अप श्रृंखला में इसका एकीकरण है, जो भारतीय स्टार्टअप्स को UAE के तेज़ी से बढ़ते नवाचार परिदृश्य से जोड़ने की एक रणनीतिक पहल है। इस पहल के तहत चुने गए स्टार्टअप्स को UAE में फास्ट-ट्रैक बिज़नेस लाइसेंसिंग, स्थानीय मार्गदर्शन तक पहुँच, निवेशक नेटवर्क और UICC के पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से इनक्यूबेशन सहायता का लाभ मिलेगा।

(ii) यह समझौता ज्ञापन ज्ञान के आदान-प्रदान, नवाचार-संचालित संस्थागत संबंधों और सीमा-पार वित्तपोषण के अवसरों के लिए एक रूपरेखा भी स्थापित करता है। दोनों संस्थान संयुक्त स्टार्टअप एक्सपो, हैकथॉन, निवेशक संपर्क और छात्र उद्यमियों तथा शुरुआती चरण के संस्थापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मिलकर काम करेंगे।

(iii) यह पहल भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 2022 में हस्ताक्षरित व्यापक CEPA समझौते के अनुरूप है, जिसने व्यापार, सेवाओं और निवेश में आर्थिक साझेदारी को गति दी है। UICC-AIC-BHU सहयोग अब CEPA के तहत एक स्टार्टअप-केंद्रित मील का पत्थर है, जिसका लक्ष्य महानगरीय क्षेत्रों से परे समावेशी विकास है।

AWARDS

1. तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले ने ओपन-सोर्स इनोवेशन के लिए दो राष्ट्रीय जीआईएस पुरस्कार जीते।

जुलाई 2025 में, तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले ने 'राष्ट्रीय भू-स्थानिक व्यवसायी पुरस्कार' और 'ओपन

सोर्स GIS कोहोर्ट पुरस्कार' दोनों प्राप्त करके राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की।

• IIT बॉम्बे, महाराष्ट्र द्वारा आयोजित 'ओपन सोर्स GIS डे' कार्यक्रम के तहत, ओपन सोर्स प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) के जिले के अग्रणी अनुप्रयोग के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए।

• भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अध्यक्ष डॉ. ए.एस.किरण कुमार की उपस्थिति में भद्राद्री कोठागुडेम जिला कलेक्टर जितेश वी. पाटिल को यह सम्मान सरकारी पहलों में GIS के सफल उपयोग के लिए दिया गया, जिससे लोक प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा।

• ये पुरस्कार IIT बॉम्बे की शिक्षा के लिए मुक्त और मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर (FOSSEE) टीम और शिक्षा मंत्रालय (MoE) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित राष्ट्रीय भू-स्थानिक पुरस्कार 2025 (संस्करण Q2) का हिस्सा थे। इन पुरस्कारों का उद्देश्य शासन और सेवा वितरण में सुधार के लिए मुक्त और मुक्त स्रोत प्लेटफार्मों का उपयोग करके कार्यान्वित प्रभावी GIS-आधारित समाधानों को सम्मानित करना है।

Key Points:-

(i) भद्राद्री कोठागुडेम को आपदा जोखिम प्रबंधन, अंतर-विभागीय समन्वय, जल संसाधन ट्रैकिंग, कृषि मानचित्रण और ग्रामीण विकास योजना जैसे क्षेत्रों में GIS के व्यापक उपयोग के लिए विशेष रूप से सराहना मिली। इसके कार्यान्वयन से स्थानीय सरकारी कार्यों और निर्णय लेने की दक्षता में सुधार हुआ।

(ii) इस कार्यक्रम में श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना बागवानी विश्वविद्यालय (SKLTHU) जैसे संस्थानों को भी सम्मानित किया गया, जिसे भू-स्थानिक शिक्षा में योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का पुरस्कार मिला, और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के तहत समुद्री GIS अनुप्रयोगों पर अपने शोध के लिए सम्मानित किया गया।

(iii) ये पुरस्कार सार्वजनिक सेवा वितरण में बदलाव लाने और डेटा पहुँच को लोकतांत्रिक बनाने में ओपन-सोर्स जियोस्पेशियल तकनीक के बढ़ते महत्व को रेखांकित करते हैं। तेलंगाना की सफलता की कहानी, विशेष रूप से भद्राद्री कोठागुडेम की, अन्य जिलों के लिए एक आदर्श उदाहरण है, जो बहु-क्षेत्रीय शासन सुधारों के लिए लागत-प्रभावी, स्केलेबल GIS उपकरणों को अपनाने का लक्ष्य रखते हैं।

2. ICAR-SBI टीम ने मृदा नमी सूचक नवाचार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता।

16 जुलाई, 2025 को, तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित ICAR-गन्ना प्रजनन संस्थान (ICAR-SBI) को कृषि प्रौद्योगिकी में उनके नवाचार के लिए प्रतिष्ठित 'राष्ट्रीय कृषि विज्ञान पुरस्कार 2025' से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार कम लागत वाले, वास्तविक समय मृदा आर्द्रता संकेतक (SMI) के विकास को मान्यता प्रदान करता है जो विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई दक्षता और फसल उपज में उल्लेखनीय वृद्धि करता है।

• यह पुरस्कार केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 'कृषि एवं संबद्ध विज्ञान में नवाचार एवं प्रौद्योगिकी' श्रेणी में प्रदान किया गया। यह समारोह

नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के 97वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था और इसमें राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी भी शामिल हुए थे।

• इस उपकरण को विकसित करने वाले ICAR-SBI के पाँच सदस्यीय वैज्ञानिक दल में डॉ. के. हरि, डॉ. डी. पुथिरा प्रताप, डॉ. पी. मुरली, डॉ. ए. रमेशसुंदर और डॉ. बी. सिंगारवेलु शामिल थे। उनका यह नवाचार मिट्टी की नमी मापने के लिए विद्युत चालकता का उपयोग करने, किसानों को सिंचाई संबंधी निर्णय लेने में मदद करने और जल-उपयोग दक्षता में सुधार लाने पर केंद्रित है।

• मृदा नमी सूचक (SMI) का तमिलनाडु भर में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जिससे सिंचाई जल के उपयोग में 15% की कमी और गन्ने की उपज में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जिससे उत्पादकता 55.8 टन से बढ़कर 60.4 टन प्रति एकड़ हो गई। लगभग ₹2,000 की कीमत वाला यह उपकरण छोटे किसानों के लिए किफ़ायती और उपयोगकर्ता-अनुकूल माना जाता है।

Key Points:-

(i) यह नवाचार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित और केंद्रीय जल आयोग के सहयोग से समन्वित, कृषक सहभागी कार्रवाई अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। इस तकनीक ने बैंगन, अनार, टमाटर और मूंगफली सहित विभिन्न फसलों में सफलता प्रदर्शित की है, जिससे इसके व्यापक रूप से अपनाए जाने की संभावनाएँ स्पष्ट होती हैं।

(ii) टीम ने डिजिटल मृदा नमी संवेदक (DSMS) नामक उपकरण का एक डिजिटल एंड्रॉइड-संगत संस्करण भी विकसित किया है, जिसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत लॉन्च किया गया है। इस संस्करण से दूरदराज के इलाकों में किसानों के लिए पहुँच और डेटा-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार होने की उम्मीद है।

(iii) मृदा नमी संकेतक को महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा और छत्तीसगढ़ सहित नौ राज्यों में पहले ही लागू किया जा चुका है। इसे राष्ट्रीय कृषक आय दोगुनी करने की रणनीति के तहत भी बढ़ावा दिया गया और जमीनी स्तर पर प्रचार-प्रसार के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान के माध्यम से कई ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया गया।

DEFENCE

1. समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए INS संध्याक मलेशिया में पहुंचा।

भारत का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत (बड़ा) (SVL), INS संध्याक, 16-19 जुलाई, 2025 तक मलेशिया के अपने पहले हाइड्रोग्राफिक मिशन पर पोर्ट क्लैंग में डॉकिंग करेगा। यह किसी भारतीय हाइड्रोग्राफिक पोत की पहली यात्रा है, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया में द्विपक्षीय समुद्री और तकनीकी सहयोग मजबूत होगा।

• INS संध्याक की यात्रा ने सर्वेक्षण तकनीकों और जल सर्वेक्षण डेटा के आदान-प्रदान सहित संयुक्त तकनीकी आदान-प्रदान के माध्यम से भारत और मलेशिया के बीच जल सर्वेक्षण सहयोग पर ज़ोर दिया। इसने भारतीय नौसेना के व्यापक राजनयिक पहुँच के तहत भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण विभाग

(INHD) और मलेशिया के राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण केंद्र के बीच संस्थागत संबंधों को मज़बूत किया।

• फरवरी 2024 में कमीशन किया गया, INS संध्याक, GRSE- गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता द्वारा निर्मित संध्याक-श्रेणी एसवीएल (सर्वेक्षण पोत - बड़ा) श्रृंखला का प्रमुख जहाज है। यह तटीय और गहरे समुद्र के सर्वेक्षण, समुद्र विज्ञान अनुसंधान, खोज और बचाव (SAR) कार्यों, आपदा सहायता में सहायता करता है, और इसमें जहाज पर अस्पताल और हेलीकॉप्टर लैंडिंग की क्षमता भी है।

Key Points:-

(i) इस पोत का विस्थापन लगभग 3,300 टन है, इसकी लंबाई 110 मीटर है, और यह 16 समुद्री मील (अधिकतम 18+ समुद्री मील) की गति से चलता है, जिसकी क्षमता 6,500 समुद्री मील है। यह मल्टीबीम इको साउंडर्स (MBES), साइड-स्कैन सोनार, ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल्स (AUVs), रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स (ROVs), डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (DGPS) और डिजिटल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम से लैस है।

(ii) यह मिशन भारत के "महासागर" (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) ढाँचे के अनुरूप है। जहाज़ पर स्वागत समारोह, चालक दल के सदस्यों का आदान-प्रदान और मलेशियाई कैडेटों के लिए शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिससे नौसैनिक कूटनीति पर ज़ोर दिया गया और भारतीय नौसेना और मलेशियाई समुद्री बलों के बीच संबंधों को मज़बूत किया गया।

(iii) अपनी तरह की यह पहली यात्रा, एक्ट ईस्ट नीति के तहत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की बढ़ती रणनीतिक उपस्थिति को पुष्ट करती है। यह स्वदेशी समुद्री क्षमताओं का प्रदर्शन करके और क्षेत्रीय जल सर्वेक्षण सहयोग में भारत के नेतृत्व को बढ़ाकर भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल का समर्थन करती है।

OBITUARY

1. ऑस्कर विजेता गीतकार एलन बर्गमैन का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

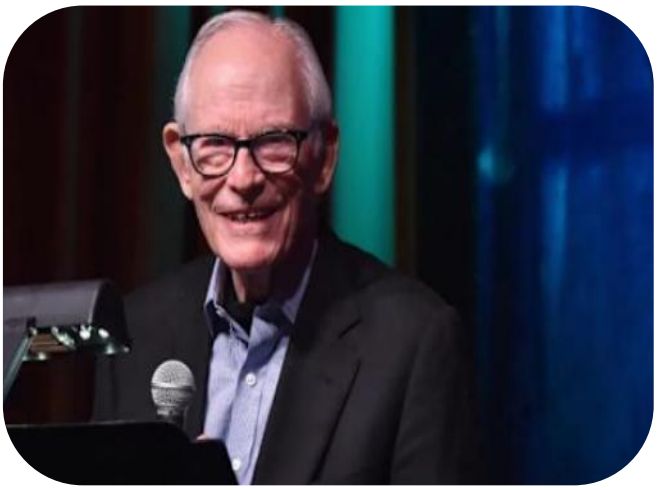

17 जुलाई, 2025 को, प्रसिद्ध अमेरिकी गीतकार एलन जे बर्गमैन का 99 वर्ष की आयु में लॉस एंजिल्स में निधन हो गया। 11 सितंबर, 1925 को ब्रुकलिन में जन्मे, उन्होंने अपनी पत्नी मर्लिन के साथ मिलकर लिखे गए पुरस्कृत गीतों की एक विरासत छोड़ी।

• छह दशकों से भी ज़्यादा समय तक, एलन ने अपनी पत्नी मर्लिन बर्गमैन के साथ मिलकर मिशेल लेग्रैंड, मार्विन हैम्लिश, क्विंसी जोन्स और डेव ग्रुसिन जैसे संगीतकारों के साथ काम किया। उनके गीतों को बारबरा स्ट्रीसैंड, फ्रैंक सिनात्रा, टोनी बेनेट, रे चार्ल्स और नील डायमंड जैसे दिग्गजों ने जीवंत किया।

• पति-पत्नी गीतकार जोड़ी, एलन और मर्लिन बर्गमैन ने अलग-अलग दशकों में तीन ऑस्कर जीतकर अकादमी पुरस्कारों में उल्लेखनीय पहचान बनाई। 1969 में, उन्होंने संगीतकार मिशेल लेग्रैंड के साथ मिलकर फ़िल्म द थॉमस क्राउन अफेयर में गाए गए गीत "द विंडमिल्स ऑफ़ योर माइंड" के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का ऑस्कर जीता।

• उनका दूसरा ऑस्कर 1974 में मार्विन हैम्लिश द्वारा रचित और इसी नाम की फ़िल्म में प्रदर्शित भावनात्मक रूप से गूँजने वाले गीत "द वे वी वेयर" के लिए आया। 1984 में, उन्होंने "येंटल" के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत संगीत का अपना तीसरा अकादमी पुरस्कार जीता, जिसमें उन्होंने एक बार फिर मिशेल लेग्रैंड के साथ काम किया।

Key Points:-

(i) ऑस्कर के अलावा, एलन और मैरिलिन ने टेलीविजन में अपने काम के लिए चार एमी पुरस्कार जीते (जैसे, सिबिल और ए टिकट टू ड्रीम) और संगीत में लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए 1997 में ग्रैमी ट्रस्टीज़ पुरस्कार प्राप्त किया।

(ii) 1925 में ब्रुकलिन में जन्मे एलन ने UNC और बाद में UCLA में संगीत की पढ़ाई की। 1950 के दशक के अंत में उनकी मुलाकात मर्लिन से हुई और 1958 में उन्होंने शादी कर ली। 1980 में उन्हें सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ़ फ़ेम में शामिल किया गया। एलन ने संगीत लिखना और रिलीज़ करना जारी रखा—उनका गायन एल्बम 'लिरिकली, एलन बर्गमैन' 2007 में आया।

(iii) एलन के परिवार में उनकी बेटी जूली और पोती हैं। महीनों तक सांस की बीमारी से जूझने के बाद, उनकी मृत्यु घर पर ही हुई, जहाँ उनकी बेटी उनके साथ थी, लेकिन उन्होंने अंत तक गीत लेखन जारी रखा।

Static GK

Bureau of Indian Standards (BIS)	महानिदेशक (DG) : प्रमोद कुमार तिवारी	मुख्यालय: नई दिल्ली
Switzerland	राष्ट्रपति: कैरिन केलर-सटर	राजधानी: बर्न
Tamil Nadu	मुख्यमंत्री: एम के स्टालिन	राज्यपाल: आर. एन. रवि
Telangana	मुख्यमंत्री: रेवंत रेड्डी	राज्यपाल: जिष्णु देव वर्मा
Ministry of Information & Broadcasting (MIB)	केंद्रीय मंत्री: अश्विनी वैष्णव	मुख्यालय: नई दिल्ली
Bihar	मुख्यमंत्री: नीतीश कुमार	राज्यपाल: आरिफ मोहम्मद खान
National Institute for Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities (NIEPID)	निदेशक : डॉ. बी.वी. राम कुमार	मुख्यालय : सिकंदराबाद, तेलंगाना
SEBI	अध्यक्ष: तुहिन कांता पांडे	मुख्यालय: मुंबई
Jio Financial Services	CEO : हितेश कुमार सेठिया	मुख्यालय: मुंबई
UAE	मुद्रा: संयुक्त अरब अमीरात दिरहम	राष्ट्रपति: मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान
Maharashtra	मुख्यमंत्री: देवेंद्र फडणवीस	राज्यपाल: सी. पी. राधाकृष्णन
Malaysia	प्रधान मंत्री: अनवर इब्राहिम	राजधानी: संघीय क्षेत्र कुआलालंपुर